फ़रीदाबाद पुलिस के पिटने का सिलसिला जारी, अब की थाना सदर की बारी

बल्लबगढ (म.मो.) पुलिस किसी को पीटती है वह तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जब कानून का पालन कराने गयी पुलिस पिटती है तो वह उससे कहीं कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता। फरीदाबाद पुलिस में यह आम होता जा रहा है।

दिनांक 10-11 मार्च की मध्य रात्रि को आईएमटी पुलिस चौकी (थाना सदर बल्लबगढ) को फ़ोन पर शिकायत मिली कि चंदावली गांव में कोई बहुत ऊंची आवाज में डीजे बजा कर सब की नींद हराम कर रहा है। तीन पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे और डीजे बजा कर नाचने वालों को डीजे बंद करने को कहा। कहा-सुनी बढ़ते हुए मार-पीट में बदल गयी। दो पुलिसकर्मी भागने में कामयाब हो गये तो एक (उस जमात) के हत्थे चढ गया। जिसे शराब व सत्ता के नशे में धुत्त होकर नाचने वालों ने खूब पीटा और उसकी वर्दी भी फ़ाड़ दी।

नाचने व पीटने वालों में मुख्य था ज़िला परिषद के चेयरमैन विनोद चौधरी का भाई जो अपने साले की लगन-सगाई समारोह में जश्न मना रहा था। घटना के बाद जब अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा तो घायल सिपाही को भीड़ के चंगुल से छुड़वाया गया तथा पुलिस पर हमला करने वालों में से 2 को मौके से गिरफ़्तार कर लिया गया जबकि बाकी 6 भाग चुके थे। इनमें से एक खुद वह था जिसकी सगाई हुई थी।

पुलिस ने मामले से सम्बन्धित वांछित कार्यवाही तो कर दी, परन्तु बड़ा सवाल यह है कि पुलिस पर इस तरह के हमले क्यों बढ रहे हैं? इसके दो मुख्य कारण समझे जाते हैं। एक तो खुद पुलिसकर्मियों के असामाजिक तत्वों से घनिष्ठता एवं उनसे लेन-देन का व्यवहार बढाना; दूसरे, राजनेताओं की दखलंदाजी। जिन राजनेताओं की चापलूसी एवं तलवे चाट कर पुलिसकर्मी मनचाही तैनाती आदि प्राप्त करेंगे तो वे कैसे उनके व उनके लग्गुए-भग्गुओं के सामने सिर उठा सकेंगे? जरूरी नहीं कि ये दोनों कारण हर वारदात के पीछे हों, उक्त दोनों कारणों अथवा करकों से एक माहौल बनता है और पुलिस की एक छवि अथवा रेटिंग तय होती है। देखने वाले फ़िर सारी पुलिस को उसी नज़र से देखते हैं। इसका खामियाज़ा कई बार वे पुलिसकर्मी भी भुगतते हैं जिन पर उक्त दोनों कारकों में से कोई भी लागू नहीं होता।

मौजूदा मामले में मुख्य आरोपी के भाई (विनोद चौधरी, चेयरमैन ज़िला परिषद) का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि गलती तो उसके भाई व रिश्तेदारों ने की है, पर पुलिस ने भी हद कर दी। चेयरमैन का अभिप्राय बड़ा स्पष्ट है। गलती, यानी पुलिस की पिटाई हो गयी सो हो गयी परन्तु पुलिस को भी मामले को बढाना नहीं चाहिये था; यानी कि पिट-पिटा कर ले-देकर समझौता करके मामले को निपटा लेना चाहिये था। यही वह मानसिकता है जिसके भरोसे इस तरह की वारदातें बढ रही हैं।

बीती दिवाली पर थाना एसजीएम नगर की चौकी नम्बर 3 के क्षेत्र में रात्रि गश्त करती पुलिस पार्टी पर केवल इसलिये कुछ लड़कों ने हमला कर दिया था कि उन्हें बहुल देर रात तक पटाखे चलाने से मना किया था। इससे भी पहले ओल्ड फ़रीदाबाद के थाने में मेवला महाराजपुर के पचासों गूजरों ने घुस कर एसएचओ सहित पुलिसकर्मियों से मारपीट इस लिये की थी कि जिस व्यक्ति को वे मारना-पीटना चाहते थे, पुलिस जिप्सी उसे लेकर किसी तरह थाने में घुस गयी थी जिसके पीछे-पीछे यह भीड़ भी थाने में चढ आई थी। उस भीड़ के पीछे स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल की पूरी ताकत थी। उसी ताकत के बल पर पहले तो हमलावरों के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी कार्यवाही को रोकने का प्रयास किया गया। प्रयास विफ़ल हुआ तो एसएचओ व डीसीपी का तबादला तुरन्त और बाद में सीपी सुभाष यादव का भी तबादला करा दिया गया।

ऐसे ही कारणों के चलते राजनीतिक शरण पाये असामाजिक तत्व जब-तब पुलिस पर हमलावर होते हैं। बीते दो वर्षों से राज्य सरकार ने भी पुलिस की गिरती कार्यक्षमता व बढते अपराधों को महसूस करते हुए अमिताभ ढिल्लों को फरीदाबाद का पुलिस कमिश्नर तैनात किया है। भरोसेमंद सूत्रों की मानें तो ढिल्लों की तैनाती मुख्यमंत्री खट्टर ने बड़े गुपचुप तरीके से केवल शत्रुजीत कपूर (पूर्व सीपी) के कहने पर की है। यदि इनकी भनक फ़रीदाबाद के राजनेताओं को लग जाती तो ये लोग खट्टर के दर पर मरन व्रत लेकर बैठ जाते। पिछले दिनों जब ये राजनेता केन्द्रीय भाजपा नेता रामलाल को लेकर खट्टर के पास ढिल्लों को बदलवाने पहुंचे तो खट्टर ने साफ़ कह दिया कि अब 6 माह तो कम से कम झेलना ही पड़ेगा। यकीनन जिन राजनेताओं की टक्साल पर ताले लग गये हों, थोने-चौकियों की दुकानदारी बंद हो गयी हो, सीपी ने फ़ोन तक उठाने बंद कर दिये हों तो वे तो कल्पेंगे ही। चुनाव भी अब बहुत दूर नहीं रह गये हैं, ऐसे में तो 6 माह भी बहुत भारी पड़ने वाले हैं।

ऐन पुलिस चौकी के सामने 'ओयो' होटल का सेक्स धंधा

पुलिस की नाक के नीचे अय्याशी का अड्डा

फ़रीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 21 ए व 21 बी की विभाजक सड़क पर, सेक्टर 21 ए में कोठी नम्बर 325 कानून के अनुसार एक रिहायशी दो मंजिला इमारत है। लेकिन कानून की उल्लंघना करके एक हज़ार गज में बनी इस कोठी में 'ओयो' होटल एवं रेस्तरां चलाया जा रहा है। केवल होटल एवं रेस्तरां ही चलता रहता तो भी आस-पास के लोग इसे बर्दाश्त कर लेते, परन्तु वहां सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक लड़कियों व लड़कों का जो आवारा तांता लगा रहता है, उससे इन सैक्टरों के निवासी बेहद परेशान हैं।

लगभग सभी लड़कियां किसी न किसी स्कूल की ड्रेस में होती हैं तथा मैट्रो रेल से आती हैं। इन्हें मैट्रो रेल स्टेशनों से होटल तक लाने के लिये होटल की ओर से बाकायदा मोटर साइकिलों व एक-दो ऊबर टैक्सियों को स्थाई तौर पर रखा गया है। अनुमान है कि स्थानीय लड़कियों के अलावा दिल्ली के स्कूलों तक से लड़कियां यहां नियमित रूप से लाई जाती हैं।

होटल के एक भीतरी सूत्र के अनुसार ये लड़कियां औसतन एक से दो घंटे ही रुकती हैं। इनके लिये ग्राहक होटल में पहले से ही तैयार रहते हैं। विश्वसनीय सूत्र के मुताबिक लड़की को 1500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पेमेंट होती है तथा कमरे का किराया 2000 रुपये (एक घंटे का) वसूला जाता है।

करीब दो-ढाई साल से चल रहा यह धंधा जब अच्छा जम गया और ग्राहकों की संख्या के मुकाबले कमरे कम पड़ने लगे तो पड़ोस में ही एक और कोठी नं. 530 भी किराये पर ले ली गयी। अक्सर ग्राहक रूपी लड़के भाड़े के 'पार्टनर' की प्रतीक्षा में पास के पार्क में भी बैठे रहते हैं।

यह सारा धंधा होटल से मात्र 50 मीटर के फ़ासले पर स्थित पुलिस चौकी के ठीक सामने चलता रहता है। भरोसेमंद सूत्र का यकीन करें तो होटल द्वारा चौकी को 60,000 रुपये मासिक केवल अपनी आंखें बंद रख कर चुप रहने के लिये दिये जाते हैं। चौकी के ही एक पुलिसकर्मी को यह कहते सुना गया कि इस बेकार सी चौकी में इसके अलावा और तो कोई कमाई का साधन है भी नहीं।

इलाके (बड़खल) की विधायक सीमा त्रिखा का घर भी इस होटल से करीब एक-डेढ किलोमीटर के फ़ासले पर है। स्थानीय लोग़ों ने इस सैक्स अड्डे की शिकायत उनसे भी की थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी तो आरडब्लूए (रेजिडेंट वैलफ़ेयर एसोसिएशन) के प्रधान गजराज नागर से शिकायत की। नागर ने कई बार थाना एनआईटी के प्रभारी व अतिरिक्त प्रभारी को फ़ोन पर सारे मामले से अवगत कराया लेकिन निकले ढाक के वही तीन पात। रिहायशी इलाके में व्यापारिक गतिविधि चलाने के विरुद्ध नागर ने 'हूडा' विभाग में भी शिकायत की तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने स्थाई लोक अदालत में केस डाल रखा है। अदालती प्रक्रिया जैसे चलती है 6 माह से चल रही है।

ग़ैर ज़रूरी ही नहीं ग़ैर क़ानूनी भी थी नोटबंदी

दिल्ली (म. मो.) नोटबन्दी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी बदहाल हुई है इसका प्रमाण चंद्र शेखर गौर की आरटीआई की जानकारी से मिलता है। पता चला है कि न्यूनतम जमा राशि नहीं रखे जाने पर ग्राहकों से जुर्माना वसूली के प्रावधान के कारण मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में करीब 41.16 लाख खाते बंद कर दिए गए हैं।

अब एसबीआई ने बढ़ते दबाव से घबराकर 1 अप्रैल से यह जुर्माना राशि 75 प्रतिशत तक घटाने का अहम फैसला किया है। गौर का कहना है कि 'अगर एसबीआई इस मद में जुर्माने की रकम को घटाने का निर्णय समय रहते कर लेता, तो उसे 41.16 लाख बचत खातों से हाथ नहीं धोना पड़ता।' बड़ी बात यह है कि एसबीआई बैंक ने अप्रैल 2017 में ही न्यूनतम बैलेंस का नियम लागू किया था।

ऐसे ही एक व्यक्ति ने आरटीआई मे जानकारी मांगी कि क्या प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और 2000 रुपये के नए नोट लाने के अपने फैसले के संबंध में राष्ट्रपति से भी चर्चा की थी, उन्हें सूचित किया था?

दरसअल ऐसा न करना भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 24 और 25 का उल्लंघन है। इस संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 (ए) में भी प्रावधान है कि इस तरह की जरूरी कोई भी सूचना राष्ट्रपति को भेजी जानी चाहिए।

उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटबंदी से संबंधित फाइल पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत अनुमोदन की प्रमाणित कॉपी मांगी थी. साथ ही दो हजार के नोटों की नई श्रृंखला लाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कानून, 1934 की धारा 24 के तहत नोटों की मौजूदा प्रचलित सूची के संशोधन के लिए स्वीकृति देने वाली कॉपी की भी मांग की थी।

लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना याचिकाकर्ता को यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी आरटीआई कानून के तहत 'सूचना' के दायरे में नहीं आती और इसे प्रकट करने से देश के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं।

अब बताइये इस बात से देश के आर्थिक हित कैसे प्रभावित हो सकते हैं?

नोटबन्दी एक ऐसा डिजास्टर स्ट्रोक था जिसने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को एक गड्ढे में पहुँचा दिया है। इससे उबरने में दशको का समय लगेगा।

निगमायुक्त ने खुली लूट के ऑडिट के लिये चुनी सड़कें, अमरीक सिंह को सलहाकार लगाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) विकास के नाम पर निगम का अधिकांश पैसा सड़कों पर ही खर्च होता आ रहा है। उसके बावजूद भी सड़कों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक सड़क जब तक बनती है तब तक चार उखड़ चुकी होती हैं। गौरतलब बात यह है कि एक ही सड़क को रोज़-रोज बनाना विकास कार्य की श्रेणी में नहीं आता। हां पहली बार कोई सड़क बने तो उसे विकास समझा जा सकता है, लेकिन फरीदाबाद में बनी-बनाई सड़कों को ही बार-बार बनाने को विकास का नाम दिया जाता है।

सड़कें बनाने का धंधा जिन लोग़ों के ज़िम्मे है, उन्होंने इसे अपनी मोटी लूट कमाई का स्रोत बना लिया है। उनकी सोच है कि यदि एक बार बनी सड़क कभी टूटी ही नहीं या 10-20 साल बाद टूटी तो वे कहां से क्या खायेंगे। इस लिये सड़कों का नियमित रूप से टूटते रहना, जल्दी-जल्दी टूटते रहना और उनको दोबारा बनवाने के लिये जनता का दबाव बनते रहना बहुत जरूरी है।

सड़क के जल्दी टूटने के लिये पहला कारण होता है बनते वक्त घटिया एवं सस्ता माल लगाना। इससे सड़क तो जल्दी टूटेगी ही ठेकेदार कमीशन भी अच्छा देगा। दूसरा काम यह कि सड़क पर पानी का खड़ा होना। सड़क ऐसी बनाई जाये कि बरसात की चार बूंद भी पड़ें तो वे सड़क पर ही बनी रहें। आस-पास की कच्ची ज़मीन का पानी भले ही सूख जाय पर सड़क पर खड़ा पानी सड़क पर ही रहना चाहिये। इसके लिये बरसात के अलावा उफ़नते सीवर और भी ज़्यादा लाभकारी होते हैं। सीवर का सड़ा पानी सड़क को कहीं ज़्यादा और जल्दी तोड़ता है। इसलिये सीवर लाइनों का जाम रहना भी इनके लिये बहुत उपयोगी रहता है।

पानी की मार का ज़्यादा असर तारकोल की सड़कों पर होता है। इसलिये सुझाव आया कि सीमेंट की सड़कें बनाई जायें। सीमेंट की सड़कें तारकोल वाली से कई गुणा अधिक महंगी पड़ने के बावजूद इस सुझाव पर अमल होने लगा। परन्तु लूट कमाई वाले भला यहां भी कहां चूकने वाले थे। यहां क्वालिटी से समझौता करके घटिया माल लगा कर अधिक कमीशन वसूला जाने लगा। परिणामस्वरूप सीमेंट वाली अनेकों सड़कों की साल के भीतर ही रोड़ियां बाहर निकाल आई। इसके साक्षात उदाहरण सेक्टर 15 ए में फ़ायर स्टेशन के बराबर वाली सड़क व प्याली चौक से 2 नम्बर वाली सड़क हैं।

निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने सड़क निर्माण कराने वाले अपने इन्जीनियरों से पार पाने के लिये अमरीक सिंहनामक एक सलाहकार को नियुक्त किया है। अमरीक सिंह 'हूडा' से रिटायर्ड चीफ़ इन्जीनियर है। इनका काम बनती सड़कों का मौके पर जाकर निरीक्षण करना है। सन्तोषजनक माल व काम न पाये जाने पर अमरीक सिंह की सिफ़ारिश पर काम को तुरन्त रोक दिया जाता है व ठेकेदार की पेमेंट भी।

सवाल यह पैदा होता है कि नगर निगम में छोटे-बड़े कुल मिलाकर 100 के करीब इन्जीनियर हैं। सभी अच्छी-खासी मोटी तनख्वाहें व अन्य सुविधायें निगम से झटक रहे हैं। इनमें से किसी भी इन्जीनियर के काम में सड़क या भवन बनाना शामिल नहीं होता। काम तो सारे ठेकेदार ही करते हैं। इंजीनियर काम तो केवल ठेकेदार की निगरानी व काम ठीक पाये जाने पर उसके बिल पास करने का है। अब जब सारी निगरानी अमरीक सिंह ने ही करनी है तो इन्जीनियरों की यह फ़ौज क्यों जनता का लहू पीने को पाल रखी है? इस फ़ौज का खर्चा तो जनता उठा ही रही थी अब सलाहाकार अमरीक सिंह का भी उठाना पड़ेगा।

अमरीक सिंह नगर निगम गुड़गांव के भी सलाहाकार हैं यानी दोनों नगर निगमों के कामों की निगरानी करते हैं। दूसरा सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या रिटायर चीफ इन्जीनियर अमरीक सिंह दोनों निगमों के मौजूदा चीफ़ इन्जीनियरों से कुछ ज़्यादा बेहतर निगरानी कर पायेंगे या ठेकेदारों के ऊपर एक ओर अतिरिक्त इन्जीनियर का 'बोझ' बढेगा?

यहां एक और जरूरी पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। घटिया निर्माण कार्यों के लिये हमेशा ठेकेदार को ही दोषी समझा जाता है जबकि असली दोषी वे अफ़सर व नेता होते हैं जो ठेकेदार को काम देते या दिलाते हैं। काम दिलाने के बदले सब को मोटा माल चाहिये जो ठेकेदार घर से तो देने से रहा, वसूली तो उसे टैंडर की रकम में चोरी से ही करनी है। जितना अधिक कमीशन ऊपर वाले वसूलेंगे उतना ही घटिया काम होगा। तभी बहुत ऊंचे ठेकेदार, जिन्हें अपनी साख की चिन्ता होती है वे तो नगर निगम के काम पकड़ते ही नहीं। ऐसे में नौसिखिया एवं अनपढ ठेकेदार काम पकड़ कर काम का सत्यानाश कर देते हैं।

अभी करीब डेढ-दो साल पहले ही सेक्टर 14-17 की विभाजक सीमेंटिड सड़क बनी थी। उसमें कम से 4 सीवर मैनहोल, बीच सड़क के ऐसे हैं जो सड़क लेवल से 3-4 इन्च नीचे बैठ कर गड्ढों की शक्ल ले चुके हैं। इनसे रात को कभी भी भयानक दुर्घटना हो सकती है। ऐसे काम के नमूने शहर भर मिल जायेंगे।

पिछले दिनो निगमायुक्त ने गलत काम करने वाले ठेकेदारों की पेमेंट रोक देने की धमकी दी थी। यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष यह है कि सही काम करने वाले ठेकेदारों की पेमेंट तो हमेशा ही रुकी रहती है। क्योंकि इंजीनियरो और अफसरों को हिस्सा पत्ती उनके मनमाफिक देने की गुंजाईश ऐसे ठेकेदार के पास नहीं होती। मोहम्मद शाइन को अगर अच्छा काम चाहिए तो अच्छे ठेकेदार लाने होंगे और अच्छे ठेकेदार तभी आयेंगे जब उन्हें समय पर बिना कमीशन दिये पेमेंट मिलता रहेगा।